

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 5/19

GCMS NO 2019/00002

ओम प्रकाश पुत्र गोपीलाल जाति महावर निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई

माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
2. महेश कुमार पुत्र शिवकुमार जाति ब्राह्मण
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत
5. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत
6. तारा कंवर पत्नि दुर्गा सिंह जाति राजपूत समस्त निवासीयान ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
7. प्रभू पुत्र रामपाल
8. कन्हैया पुत्र रामपाल
9. रामलाल पुत्र रामपाल समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
10. आनन्दीलाल पुत्र मूलचंद जाति माली निवासी मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
11. प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 1035/18 निर्णय दिनांक 21.12.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)  
अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम बैष्णव  
अभिभाषक रेस्पो0 श्री श्री रमेश चंद गोयल, श्री सुरेन्द्र सिंह जौदान, श्री भगवानदास माली

दिनांक 18.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.12.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम मित्रपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6200 है0 भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा न0 758,759,1143,1144,1148,1209,1211,1212 कुल किता 8 कुल रकबा 1.5900 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा न0 382 की भूमि है। ग्राम मित्रपुरा मे खसरा न0 382 बहुत बडा रकबा है जिसमे कई खातेदार है। तथा कई टुकडे मौके पर हो रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 की भूमि साथ साथ खसरा न0 1144

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



रकबा 0.31 , 1143 रकबा 0.27, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 भूमि पर भी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण का हमारे खेतों के मध्य कोई कब्जा नहीं है। हमारे खेतों के पीछे की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में अप्रार्थीगण संख्या 3 का कब्जा एवं अधिकार है। उक्त भूमि के खसरा नं० 382 की ही भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 की कब्जाशुदा भूमि को गहरी लाल लाईन से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि को नीली लाईन से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में मार्क क भूमि जो मूल खसरा नं० 1144 रकबा 0.31 है0, 1143 रकबा 0.27 है0, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता की 0.66 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकार क्षेत्र में है। तथा नजरी नक्शा में दिखाया गया भाग मार्क ख हम प्रार्थीगण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त हिस्सा अदल बदल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने इस हिस्से को आपसी सहमति से बिना कब्जे के विभाजन रिकार्ड पर कर लिया है। मौके पर विभाजन नहीं है जबकि मौके पर हम काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। बिना कब्जे की ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 में खसरा नं० 1144, 1143, 1211 व अन्य सहित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 10.9.18 को बेचान कर दिया है। जिसका कोई विधिक आधार नहीं है जो अप्रार्थी संख्या 7 को किया गया है। जिसका कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण को तथाकथित बेचान दिनांक 10.9.18 की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 7 से सम्पर्क किया कि आपने बिना कब्जे एवं अधिकार के किसी प्रकार विभाजन करवा कर बेचान कर दिया है जिसके कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 तथा 7 को ताफैसला वाद इस अमर से पाबंद किया जावे कि ग्राम मित्रपुरा के ख० न० 1134 रकबा 0.31 है0, 1143 रकबा 0.27 है0, 1211 रकबा 0.08 है0 भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे तथा किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश नहीं करे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्प० संख्या 1 ता 6 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणों की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सुस्थापित सिद्धान्तों के एवं तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्प० संख्या 1 ता 6 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्वयं की मर्जी से एवं बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में साबित मानकर अहम कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्प० संख्या 1 ता 6 ने अपने मामले को प्रथम दृष्टया मामला किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेसपो 1 ता 6 के द्वारा केवल स्वयं के द्वारा हाथ से बनाये गये कच्चा नजरी नक्शा जो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है केवल कच्चे नजरी नक्शा जो रेसपो 1 ता 6 द्वारा हाथ से बनाया है के आधार पर स्वयं की मर्जी से प्रथम दृष्टया मामला रेसपो 1 ता 6 के पक्ष में साबित मानकर अहम कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत व रेसपो संख्या 7 ता 10 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.9.18, जमाबंदी सम्वत 2075-78 खाता संख्या नया 87 ग्राम मित्रपुरा, नक्शा ट्रेस, नामा संख्या 367,368,369 दिनांक 22.11.18 का वर्णन जानबूझकर आदेश में नहीं किया है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलांत ओमप्रकाश खातेदार काशतकार व काबिज है। तथा उपरोक्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांत ओमप्रकाश के पक्ष में बखूबी साबित है। अपीलांत अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उसने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से ही उपरोक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल देकर खरीद किया है तथा कब्जा प्राप्त किया है। उपरोक्त आराजीयात का नामा संख्या 367,368,369 दिनांक 22.11.18 से खातेदारी अपीलांत ओमप्रकाश के नाम दर्ज हो चुकी है। जिसका अमल जमाबंदी सम्वत 2075-78 खाता संख्या नया 78 ग्राम मित्रपुरा में हो चुका है। अपीलांत अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेसपो संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के व माननीय राजस्व मंडल अजमेर व उच्च न्यायालय के विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थी अपीलांत को उसके कब्जे काशत व खातेदारी की जमीन पर जाने के लिए विधि के विपरीत जाकर पाबंद करने में अहम भूल की है। जबकि कानूनन खातेदार काशतकार को उसकी स्वयं की खातेदारी की जमीन के उपयोग उपभोग करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेसपो संख्या 1 ता 6 ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता संख्या नया 5 खाता संख्या पुराना 5 ग्राम मित्रपुरा पेश की है जिसमें खसरा नं 1145,1146,1149,1206,1207,1208 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 3.62 है 0 के रेसपो संख्या 10 आन्नदी लाल पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/2, तथा रेसपो मोहन सिंह हिस्सा 1/6, महेश कुमार 1/5, नरेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पिसरान दुर्गा सिंह, तारा कंवर बेवा दुर्गा सिंह का हिस्सा 1/6 दर्ज है। उपरोक्त सभी व्यक्ति सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं जिनकी उपरोक्त आराजीयात शामिल होती खातेदारी दर्ज है इसी तरह से जमाबंदी 2071-74 खाता संख्या नया 124 खाता संख्या पुराना 121 ग्राम मित्रपुरा पेश की है जिसमें खसरा नं 1142,1147 कुल रकबा 1.71 है 0 रेसपो मोहन सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/3, नरेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, तारा कंवर बेवा दुर्गा सिंह हिस्सा 1/3 तथा महेश कुमार पुत्र शिवकुमार का 1/3 हिस्सा दर्ज शामिल दर्ज है। उपरोक्त सभी व्यक्ति सामान्य वर्ग के हैं। जिनका अपीलांत की आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। रेसपो संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है जिनकी आराजीयात व कब्जे काशत की खातेदारी के खाता संख्या व खसरा अलग है। अपीलांत अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसकी जमीन के खाता संख्या व खसरा अलग है। रेसपो संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से प्रथम दृष्टया

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई मधोपुर

मामला उनके पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 1035/18 निर्णय दिनांक 21.12.18 उनवान मोहन सिंह वगैरे बनाम प्रभू वगैरे निरस्त फरमाया जावे।



रेस्पो० के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा न० 382 की भूमि है। ग्राम मित्रपुरा में खसरा न० 382 बहुत बड़ा रकबा है जिसमें कई खातेदार हैं। तथा कई टुकड़े मौके पर हो रहे हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 आन्नदी लाल की खातेदारी की भूमि खसरा न० 1145, 1146, 1149, 1206, 1207, 1208 की भूमि साथ साथ खसरा न० 1144 रकबा 0.31, 1143 रकबा 0.27, 1211 रकबा 0.08 है कुल कितना 3 कुल रकबा 0.6600 है भूमि पर भी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण का हमारे खेतों के मध्य कोई कब्जा नहीं है। हमारे खेतों के पीछे की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा एवं अधिकार है। उक्त भूमि के खसरा न० 382 की ही भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में मार्क क भूमि जो मूल खसरा न० 1144 रकबा 0.31 है, 1143 रकबा 0.27 है, 1211 रकबा 0.08 है कुल कितना की 0.66 है भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकार क्षेत्र में है तथा नजरी नक्शा में दिखाया गया भाग मार्क ख हम प्रार्थीगण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त हिस्सा अदल बदल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने इस हिस्से को आपसी सहमति से बिना कब्जे के विभाजन रिकार्ड पर कर लिया है। मौके पर विभाजन नहीं है जबकि मौके पर हम काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। बिना कब्जे की ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 में खसरा न० 1144, 1143, 1211 व अन्य सहित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 10.9.18 को बेचान कर दिया है। जिसका कोई विधिक आधार नहीं है जो अपीलांत को किया गया है। जिसका कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है। उक्त तथाकथित बेचान की आड में अपीलांत रेस्पो० को उनके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं प्राईमाफेसी केस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित माना गया है। अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी/रेस्पो० का प्रार्थना पत्र खारिज हो सके। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा न० 382 का ही भाग है। जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी/रेस्पो० अधिवक्ता का कथन रहा कि भूमि खसरा न० 1134, 1143, 1211 पर प्रार्थी/रेस्पो० संख्या 1 ता 6 का ही कब्जा काश्त है। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा बिना किसी अधिकार के विभाजन कराया जाकर

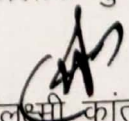
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान किया गया है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। जबकि अपीलांट के अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की अस्वीकृत खातेदारी की आराजीयात रही है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्होंने विधिवत रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.9.18 को प्रतिफल प्राप्त किया जाकर अपीलांट को बेचान किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के विवादित भूमि प्रभूकन्हैया पिसरान रामपाल हिस्सा 2/3 बिला रहन रामलाल पिसरान रामलाल हिस्सा 1/3 जाति बैरवा सा.देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। जिसको खातेदारों द्वारा भूमि का विक्रय अपीलांट ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल महावर के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हस्तान्तरण किया गया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध छाया प्रति विक्रय पत्र से होती है। प्रार्थीगण/रेस्पो 1 ता 6 का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कभी कब्जा काशत नहीं रहा है शुरू से ही प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या 1 ता 6 का रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात पर कब्जा होने से कब्जेधारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है बल्कि वह अतिचारी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि जरिये नामा 0 अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 से होती है। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। विवादित आराजीयात पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज रही है वह भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे एवं वर्तमान खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज है वह भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जबकि प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है। कानूनन अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमियों पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1035/18 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.18 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(लक्ष्मी कान्त बालोत)  
संजय अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर